

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण

अपील संख्या:- 152 / 2022

1. रामलाल बुदेला पुत्र मूलचंद, उम्र 70 साल,
2. रंजना देवी पत्नी रामलाल बुंदेला, उम्र 67 साल,
जाति खटीक, निवासीगण 2/8 हाउसिंग बोर्ड, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं, हाउसिंग
4. मोहल्ला खटीकान, बगड़, तहसील व जिला झुंझुनूं।

बनाम

1. भरत बुदेला पुत्र रामलाल बुंदेला, उम्र 40 साल
2. सुनिता बुदेला पत्नी भरत बुंदेला, उम्र 38 साल,
जाति खटीक निवासीगण 2/8 हाउसिंग बोर्ड झुंझुनूं।
3. अम्बेडकर बुंदेला पुत्र रामलाल बुंदेला, उम्र 36 साल,
4. संतोष बुंदेला पत्नी अम्बेडकर बुंदेला, उम्र 32 साल, जाति खटीक, निवासीगण 2/8 हाउसिंग
झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 14.09.2022 बअदालत उपखण्ड अधिकारी पीठासीन भरण-पोषण झुंझुनूं उनवानी मु. रामलाल वगै० बनाम भरत बुदेला वगै० मु०न० 6/22 आवेदन पत्र बाबत धार अभिभावकों और व० नाग० का भरण पोषण

उपस्थित:-

1. श्री मुकर्रम अंसारी, एडवोकेट- अपीलान्ट्स की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोजेन्ट सं० 1 लगायत 4 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक

उक्त विषयक अपील विद्वान उपखण्ड मजिस्ट्रेट झुंझुनूं के आदेश दिनांक 14.09.2022 प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की ओर से अपील निम्न प्रकार से पेश है कि अदालत मातहत विरुद्ध कानून, पत्रावली, व न्याय है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि वरिष्ठ नागरिक है तथा रेस्पोजेन्टगण के माता पिता व सास ससुर है जिसकी देखभाल करने के तरीके से उनका भरण-पोषण करने का दायित्व रेस्पोजेन्टगण पर था और अपीलान्ट्स को नौकरी के दौरान रेस्पोजेन्ट्स की हर इच्छा व आवश्यकताओं की पूर्ति की है। इसके बावजूद अपीलान्ट्स साथ मारपीट करना, गाली गलोच करना व घर से बेदखल करना तथा हैरान व परेशान किया ही गलत है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया है कि रेस्पोजेन्ट्स नं० 1 व 2 मकान अपीलान्टगण का स्वअर्जित आय से प्लाट लेकर निर्माण करवाया गया था। जिससे बेदखल कोई कानूनी अधिकार रेस्पोजेन्ट नं० 1 व 2 को नहीं है। जिसका कब्जा दिलाया जाना तथा उसको नहीं रोकने बाबत रेस्पोजेन्ट नं० 1 व 2 पाबन्द किया जाना उचित व न्यायोचित था। अपीलान्ट सेवानिवृत्त व्यक्ति है जिसने अपनी पेंशन से ऋण उठा कर रेस्पोजेन्ट्स नं० 1 को विदेश ईटल

लिए ऋण राशि दे दी जिसकी अदायगी रेस्पोडेन्ट्स नं० 1 व 2 के द्वारा नहीं किए जाने की स्थिति में अपीलान्ट्स की पेंशन राशि से उक्त ऋण राशि की कटौती हो जाने के कारण अपने जीवन यापन के लिए रेस्पोडेन्ट्सगण पर आश्रित होना पड़ रहा है और रेस्पोडेन्ट्स द्वारा भरण-पोषण नहीं किए जाने से भारी आर्थिक समस्या का सामाना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स को रेस्पोडेन्ट्सगण से प्रति माह बतौर भरण-पोषण 50,000/- रुपये दिलाया जाना उचित व न्यायोचित था। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि अपीलान्ट्स सं० 1 से स्वअर्जित सम्पत्ति पर लोन उठवा कर लोन की राशि हड़पने संबंधी अनुतोष तथा अप्रार्थी नं० 1 व 2 को प्लॉट नं. 2/8 हाउसिंग बोर्ड झुंझुनूं से बेदखल करने का इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है। परन्तु भरण पोषण दिलाये जाने का अधिकार और सम्पत्ति का कब्जा दिलाया जाना था ऐसा नहीं किया गया है। धारा 23 कतिपय परिस्थितियों के अन्तरण का होना जहां कोई वरिष्ठ नागरिक जिसने इस अधिनियम का प्रारम्भ व पश्चात् अपनी सम्पत्ति का दान करने में या अन्यथा अन्तरण इस शर्त के अधीन रहते हुए किया है कि अतिरिक्त अतरक को बुनियादी सुविधाएं और बुनियादी भौतिक आवश्यकताओं प्रदान करेगा और ऐसा अतिरिक्त ऐसी सुख सुविधाओं तथा भौतिक आवश्यकता प्रदान करने से इन्कार करेगा या असफल रहेगा तो सम्पत्ति का उक्त अन्तरण कपट या प्रतीक या अनावश्यक प्रभाव के अधीन किया गया समझा जावेगा और अन्तरण के विकल्प पर अधीकरण द्वारा शून्य घोषित किया जायेगा। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट रद्द किया जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 14.09.2022 को अपास्त किया जाकर अपीलान्टको भरण-पोषण रेस्पोडेन्ट्स से पचास हजार रुपये प्रति माह व रेस्पोडेन्ट नं० 1 व 2 द्वारा जबरन किया कब्जा मकाने से हटाकर अपीलान्ट को दिलाया जावे।

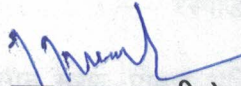
बहस सुनी गई। अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क किया कि अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि अपीलान्ट वरिष्ठ नागरिक है रेस्पोडेन्टगण के माता पिता व सास ससुर है जिसकी देखभाल करना व उचित तरीके से भरण-पोषण करने का दायित्व रेस्पोडेन्टगण पर था और अपीलान्ट नं० 1 द्वारा अपनी नौकरी के रेस्पोडेन्ट्स की हर इच्छा व आवश्यकताओं की पूर्ति की है। इसके बावजूद अपीलान्ट्स के साथ मरना, गाली गलोच करना व घर से बेदखल करना तथा हैरान व परेशान किया जाना बहुत ही गलत अदालत मातहत ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया है कि रेस्पोडेन्ट्स नं० 1 व 2 ने निर्मित अपीलान्टगण का स्वअर्जित आय से प्लॉट लेकर निर्माण करवाया गया था। जिससे बेदखल करने का कानूनी अधिकार रेस्पोडेन्ट नं० 1 व 2 को नहीं है। जिसका कब्जा दिलाया जाना तथा उसमें रहने से रोकने बाबत रेस्पोडेन्ट नं० 1 व 2 पाबन्द किया जाना उचित व न्यायोचित था। अपीलान्ट नं० 1 सेवक व्यक्ति है जिसने अपनी पेंशन से ऋण उठा कर रेस्पोडेन्ट्स नं० 1 को विदेश ईटली जाने के लिए पेंशन राशि दे दी जिसकी अदायगी रेस्पोडेन्ट्स नं० 1 व 2 के द्वारा नहीं किए जाने की स्थिति में अपीलान्ट पेंशन राशि से उक्त ऋण राशि की कटौती हो जाने के कारण अपने जीवन यापन के लिए रेस्पोडेन्ट्स पर आश्रित होना पड़ रहा है और रेस्पोडेन्ट्स द्वारा भरण-पोषण नहीं किए जाने से भारी आर्थिक समस्या का सामाना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स को रेस्पोडेन्ट्सगण से प्रति माह भरण-पोषण 50,000/- रुपये दिलाया जाना उचित व न्यायोचित था। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि अपीलान्ट्स सं० 1 से स्वअर्जित सम्पत्ति पर लोन उठवा कर लोन की राशि संबंधी अनुतोष तथा अप्रार्थी नं० 1 व 2 को प्लॉट नं. 2/8 हाउसिंग बोर्ड झुंझुनूं से बेदखल करने का न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है। परन्तु भरण पोषण दिलाये जाने का अधिकार और सम्पत्ति का कब्जा दिलाया जाना था ऐसा नहीं किया गया है। धारा 23 कतिपय परिस्थितियों के अन्तरण का शून्य होना जहां कोई वरिष्ठ नागरिक जिसने इस अधिनियम का प्रारम्भ व पश्चात् अपनी सम्पत्ति का दान करने में या अन्यथा अन्तरण इस शर्त के अधीन रहते हुए किया है कि अतिरिक्त अतरक को बुनियादी सुख सुविधाएं और बुनियादी भौतिक आवश्यकताओं प्रदान करेगा और ऐसा अतिरिक्त ऐसी सुख सुविधाओं तथा भौतिक आवश्यकता प्रदान करने से इन्कार करेगा या असफल रहेगा तो सम्पत्ति का उक्त अन्तरण कपट या प्रतीक या अनावश्यक प्रभाव के अधीन किया गया समझा जावेगा और अन्तरण के विकल्प पर अधीकरण द्वारा

घोषित किया जायेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर अदालत मातहत का आदेश दिन 09.2022 को अपास्त किया जाकर अपीलान्टको बतौर भरण-पोषण रेस्पोंडेन्ट्स से पचास हजार रूप माह व रेस्पोंडेन्ट नं0 1 व 2 द्वारा जबरन किया गया कब्जा मकाने से हटाकर अपीलान्ट को दिलाया

रेस्पोंडेन्ट सं0 1 लगायत 4 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। रेस्पोंडेन्ट सं0 1 लगायत विरुद्ध एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पक्षकारान पर बगौर मनन किया अदालत द्वारा पूर्ण सुनवाई कर परिस्थितियों को मध्यनजर रख कर आदेश दिनांक 14.09.2022 पारित कि अपीलान्ट रामलाल बुन्देला बैंक मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त हुआ है। अपीलान्ट अपने स्वयं के पोषण के लिए स्वयं सक्षम है। हम अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय को उचित मानते हैं। अदालत मातहत के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की यह अपील सारहीन है। अतः अपीलान्ट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 14.09.2022 यथावत रखा जाता है। रिकार्ड मातहत अदालत को आदेश की प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 13.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एल0एस0 कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूर
जिला कलक्टर